



## चिंतन मनन

## आंदोलन का रुख

दिल्ली के सिंधु बांडर से लेकर टीकरी बॉर्डर और यहां तक कि गांजीर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा अब भी है। कभी टेट बढ़ते तो कभी घटते हैं, कभी ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ जाती तो कभी घट जाती है, किसानों की तादाद भी घटती-बढ़ती रहती है, आंदोलन की रूपरेखा भी काफी कुछ बदल गई, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वो है किसानों का रुख, जो अब भी कहते हैं कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती, तब तक वो बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। पिछले माह जब केंद्र सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतारी की थी, तो लगा था कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे और नए कानूनों पर भरोसा जताएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगें को लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन के लिए ठोस हल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। सवाल है कि किसान जिन सवालों को केंद्र में खिलाकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वह सही है। दरअसल, किसानों की एक सबसे अहम मांग यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को लेकर एक विशेष कानून बनाए। इस विहार से सरकार कह सकती है कि उसने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतारी करके किसानों के हित में ठोस कदम उठाया है और ऐसा करके उसने आंदोलन कर रहे किसानों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। यह गोरतलब है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा हर साल का एक नियमित अभ्यास रहा है। इसके तहत साल भर में दो बार फसलों पर इस तरह के समर्थन मूल्य में इजाफे की घोषणा होती है। हालत यह है कि पिछले कई महीने से सरकार और किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर तक बंद है। इसके बावजूद किसान तीनों एवं कृषि कानूनों को खटकारने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जिताने के लिए एक बात है कि अब तक सरकार को एक विशेष कानून बनाए गए हैं, जो किसानों को सहमत कर दे और वे अपना आंदोलन वापस ले लें। जाहिर है, तीनों एवं कृषि कानूनों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने के मुद्दे पर सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं रखा है, जिस पर किसान अपनी मांगों के संदर्भ में विचार करने पर तैयार हों। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री के लागतार दूसरी बार संकेत के जरूर सरकार यह दर्शानी चाहती है कि वह इस मस्ले पर गंभीर है तो किसन धन सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ताजा बढ़ोतारी को किसान आंदोलन की मांगों के प्रति सरकार के रुख में लचीलेपन के तौर पर देखना शायद जल्दबाजी होगी।

## है सबका अधिकार!



अपने-अपने धर्म चलें ।  
है सबका अधिकार ॥

पर जबरन प्रवेश ।  
है फिर तो धिक्कार ॥  
अपने मन का मालिक ।  
और स्वयं की इच्छा ॥  
जबरदस्ती ठीक नहीं ।  
हो कोई भी दीक्षा ॥  
गुनहगार जो मिल रहे ।  
कड़ी सबक सिखाना ॥  
मकसद यदि जहरीले ।  
वादा फिर निभाना ॥  
शांति और सद्ब्राव का ।  
रहे हमेशा ध्यान ॥  
उठे न कोई उंगली ।  
संज्ञा जो महान ॥

-कृष्णोद्द राय

# असली मकसद जमीन घोटाला नहीं श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीराम मंदिर का विरोध करना है

भाजपा ने राम मंदिर निर्माण का अपना बड़ा वादा पूरा किया है और योजना के अनुसार 2024 से पहले अंयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर बच्य श्रीराम मंदिर बन भी जायेगा। जाहिर-सी बात है कि इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा। इसके साथ ही छह-सात महीने बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे तब भी भाजपा राम मंदिर बनाने का अपना बादा पूरा करने की बात मानदाताओं को बाद लियायी गई। ऐसे में इसकी बातें भी जायेगी। जाहिर-सी बात है कि इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा। इसके साथ ही छह-सात महीने पर भरोसा जताएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांगों पर लेकर आज भी मर्चे पर डटे हैं, दूसरी ओर सरकार ने इस मस्ले पर जो रुख अधिकायार किया हुआ है, वह समस्या का विचार किया हुआ है। आंदोलन का दिन लागतार बढ़ता जा रहा है और सहमति की गुजारिश उसी तरह खत्म होती जा रही है। आंदोलन का समाधान क्या हो, यह बहस का विषय जरूर है। यह अपने आप में विचित्र है कि एक ओर किसान अपनी मांग



